AIR should broadcast regular programmes on the above lines.

(v) Negotiation between Management and Unions for settlement of wages in Central Sector Enterprises.

DR. A. KALANIDHI (Madras Central) : In the wake., of expiry of wage agreements in various Central public sector enterprises all over India wage negotiations are being carried on. There is actually a deadlock in the dialogue mainly due the guidelines imposed by the Bureau of Public Enterprises. According to the guidelines, the managements cannot offer more than 100% of previous year's wages and DA neutralisation at Rs. 1.30 per all India consumer price index. This fitment benefit on the revision should range only between Rs. 35/- and Rs. 75/- and the minimum and maximum should be Rs. 598/- and Rs. 1419/-, the settlement should be given effect to from the date of signing the settlement ; it is also empasised that a system of production-linked wages be introduced. This is an imposition of pre-concluded decision on the working class and jeopardises the very collective bargaining system. It amounts to signing on the dotted lines imprinted by the Bureau of Public Enterprises and discussions in the industry level have, therefore, no meaning at all. It is reported that Government is going to appoint a commission to decide the quantum in the matter of DA neutralisation. Appointment of such a Commission will prolong the negotiations already delayed. I appeal to the Hon. Finance Minister to bestow his attention on this burning issue and allow the managements and unions to negotiate freely, based on the paying capacity and on the principle or collective bargaining for arriving at their own wage settlements.

(vi) Primary School Teachers' strike in Delhi

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : दिनांक 29 अप्रैल 1983 को लोक सभा में शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने दिल्ली में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए जो वक्तव्य दिया था उसमें कहा गया था :—

"माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि शिक्षकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 28 अप्रैल, 1983 को दिल्ली के उप-राज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद के साथ हुई और पदोन्नति के व्यापक अवसरों के लिए मांगों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय, शिक्षक प्रतिनिधियों की सहमति से लिया गया है ।"

किंतु हड़ताली अध्यापकों के एक प्रतिनिधि ने मुझे बताया है कि 28 अप्रैल 1983 को उप-राज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद के साथ कोई वार्ता नहीं हुई । वार्ता 29 अप्रैल को हुई जबकि अध्यापकों के प्रतिनिधियों को तिहाड़ जेल से निकालकर उप-राज्यपाल से मिलने के लिए पुलिस द्वारा ले जाया गया ।

29 अप्रैल को सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया गया उससे यह धारणा बनी थी कि दिल्ली प्रशासन और हड़ताली अध्यापकों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है और शीघ्र ही कोई समझौता हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो जाएगी ।

पिछले दो दिनों की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि प्राथमिक शिक्षकों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार का रवैया असहानुभूतिपूर्ण है वह उनकी सभी उचित मांगों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है ।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मेरी मांग है कि शिक्षा तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री सदन में बयान देकर यह स्पष्ट करें कि हड़ताली अध्यापकों से वार्ता 28 अप्रैल को हुई थी या 29 अप्रैल को हुई थी। राज्य मंत्री यह भी बताएं कि प्राथमिक अध्यापकों की मांगों पर विचार के लिए जिस सत्यम कमेटी का निर्माण हुआ था उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

हड़ताली अध्यापकों को नौकरी से हटाये जाने के आदेश वापस लेने तथा हड़ताल के दिनों का वेतन न काटने के विषय में भी स्पष्ट आश्वासन आवश्यक है।

(vii) Sanction of Payment of overtime to the Employees of India Government Mint, Calcutta

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the employees of the India Government Mint, Calcutta, have been for years legitimately demanding computation of their overtime wages for work done beyond the prescribed hours at the time rate, that is, basic pay, D.A., special pay, if any, CCA and HRA taken together. The employees of the Hyderabad Mint as well as of Bombay Mint are being paid overtime wages computed at time rate. Recently, the Government has taken a decision to sanction payment of overtime wages at time rate including HRA ; only the employees of the Calcutta Mint have been singled out and are not being given overtime wages on the basis which is applied to all the employees of the remaining India Government Mints, including Nasik Security Press.

The employees of the Calcutta Mint are being discriminated against and repeated representations have been made, but to no avail. The employees of the Calcutta Mint have obtained a decision in their favour from the District Court at Alipore on the identical question which was before the Supreme Court, but the Government preferred an appeal therefrom in the Calcutta High Court, which is pending since 1968. On the plea of the pending appeal, Government is not honouring the decree of the district court, while permitting identical facilities to the employees of other Mints and denying the same to the employees of the Calcutta Mint.

I would urge upon the Government to immediately sanction payment of overtime wages on the basis of proper computation, that is, including HRA, otherwise the resentment caused amongst the employees will affect production which the employees wish to avoid.

(viii) Measures to control floods in Gorakhpur and Basti disiricts of Uttar Pradesh

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : पिछले दो साल से लगातार आने वाली भयंकर बाढ़ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती जिले के अधिकांश भाग को तबाह और बरबाद कर दिया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रापती और उसकी सहायक रोहिणी और दूसरे छोटे-छोटे नदी नाले दो साल से लगातार तबाही ला रहे हैं। करीब-करीब एक ही स्थान पर इनके तटबंध टूटते हैं या काट दिए जाते हैं। रापती का जलग्रहण क्षेत्र जो अधिकांश पड़ौसी नेपाल में है पर नियंत्रण के लिए नैपाल सरकार से वार्ताओं का सिलसिला करीब पन्द्रह साल से चल रहा है। करनाली पर भालू बांध और पंचेश्वर बांध बनाने और बिजली पैदा करने के लिए बड़ी योजना पर अब तक कोई समझौता नहीं हो सका। लेकिन अभी हाल की सचिव स्तर की वार्ता से कुछ उम्मीद जरूर बंधी है। फिर भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इन योजनाओं पर आखिरी शक्ल देने में अभी और कितना समय लगेगा। इस बीच केन्द्र सरकार को कोई ऐसी योजना अवश्य बनानी चाहिये जिससे नेपाल सरकार को बीच में लाए बिना इस क्षेत्र के निवासियों की हर साल की विपदा